कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड व अन्य

बनाम

मैसर्स दीपक केबल्स (इंडिया) लिमिटेड,

(सिविल अपील संख्या- 4424/2014)

अप्रैल 07, 2014

[अनिल आर. दवे और दीपक मिश्रा, जे.जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धारा 11(6)- मध्यस्थ की नियुक्ति- पक्षकारों के बीच विवाद- प्रतिवादी मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग कर रहा है- अपीलकर्ता द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि समझौते में मध्यस्थता के लिए प्रावधान नहीं है- माना गया: समझौते के खंड 48 में प्रावधान है कि जब कोई विवाद या मतभेद हो कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरा होने के बाद या अनुबंध की समाप्ति, परित्याग या उल्लंघन के पहले या बाद में कार्य के प्रदर्शन से संबंधित पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाली स्थिति को इंजीनियर द्वारा संदर्भित और निपटारा किया जाना है- वहाँ यह भी शर्त है कि इस प्रकार निर्दिष्ट प्रत्येक मामले के संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा और काम पूरा होने तक पार्टियों पर बाध्यकारी होगा और ठेकेदार द्वारा इसे प्रभावी किया जाना आवश्यक है जो उचित परिश्रम के साथ काम को आगे बढ़ाएगा। इस खंड में दूर-दूर तक यह इंगित करने के लिए कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई थी  कि संबंधित

इंजीनियर को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए या दोनों पक्षों की प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए एक निर्णायक के रूप में न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता थी- यह केवल दर्शाता है कि उक्त खंड देरी से बचने के लिए तैयार किया गया था और काम को रोकना और काम को सुचारू रूप से चलाने में सुविधा प्रदान करना- खंड में प्रयुक्त भाषा ने विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए पार्टियों के इरादे को स्पष्ट नहीं किया- इसके अलावा समझौते के खंड 4.1 में कहा गया है कि यह विशेष रूप से पार्टियों द्वारा और उनके बीच समझौते से उत्पन्न होने वाले या विषय वस्तु को छूने वाले सभी मतभेद या विवाद एक समझौते का निर्णय बैंगलोर में एक सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, इस प्रकार, खंड 48, जिसे खंड 4.1 के साथ पढ़ा जाता है, स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि समझौते में कोई मध्यस्थता खंड नहीं था।

अपीलकर्ता संख्या 1, एक राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता द्वारा सब-स्टेशनों की स्थापना के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी। प्रतिवादी-कंपनी सफल बोलीदाता थी और उसके साथ अनुबंध किया गया था। विवाद उत्पन्न हुआ और प्रतिवादी ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(5) और (6) के तहत आवेदन दायर किया। अपीलकर्ता ने इस आधार पर आवेदन का विरोध किया था कि खंड 48 में मध्यस्थता का प्रावधान नहीं है और इसे मध्यस्थता खंड के रूप में नहीं माना जा सकता है। उच्च

न्यायालय ने माना कि खंड 48 को पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि यह मध्यस्थता खंड की प्रकृति में भाग लेता है और तदनुसार, विवाद में मामलों का फैसला करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। इसलिए ये अपीलें की जाती हैं।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया

1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 में कहा गया है कि जब तक मध्यस्थता समझौता यह निर्धारित नहीं करता है कि पक्ष उन सभी या कुछ विवादों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं जो उत्पन्न हुए हैं या जो परिभाषित कानूनी संबंधों के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वे संविदात्मक हों या नहीं, किसी मध्यस्थ का संदर्भ नहीं हो सकता। यह बताता है कि विवादों को मध्यस्थ के पास भेजने के लिए सहमति व्यक्त करते हुए इरादा होना चाहिए। किसी समझौते में मध्यस्थता खंड की अनुपस्थिति में, जैसा कि धारा 7 की उप-धारा (4) में परिभाषित किया गया है, पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद/विवादों को विवाद के निर्णय के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को नहीं भेजा जा सकता है। [पैरा 9] [779-एफ-एच; 780-ए]

2. खंड 48 इस आशय का है कि यह पार्टियों को अनुबंध के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रावधान करता है। यह पहला भाग है. दूसरा भाग यह है कि

जब कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरा होने के बाद या अनुबंध की समाप्ति, परित्याग या उल्लंघन के पहले या बाद में कार्य के प्रदर्शन से संबंधित अनुबंध के पक्षों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो इसे इंजीनियर के पास भेजा जाना है और इंजीनियर द्वारा उसका निपटारा किया जाना है, जो किसी भी पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने पर, मालिक और ठेकेदार को तीस दिनों के भीतर अपने निर्णय की सूचना देगा। एक शर्त यह भी है कि निर्दिष्ट प्रत्येक मामले के संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा और काम पूरा होने तक पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और ठेकेदार द्वारा इसे प्रभावी किया जाना आवश्यक है जो उचित परिश्रम के साथ काम को आगे बढ़ाएगा। पक्षकारों की मंशा को समझने के लिए खंड का यह हिस्सा महत्वपूर्ण है। इस अभिधारणा का अध्ययन करने पर, यह चित्रात्मक रूप से स्पष्ट है कि यह ऐसी कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है जो दूर से संकेत दे कि संबंधित इंजीनियर को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए न्यायिक रूप से एक निर्णायक के रूप में कार्य करने या दोनों की प्रस्तुतियों पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इंजीनियर का निर्णय केवल कार्य पूरा होने तक बाध्यकारी होता है। यह केवल ठेकेदार पर बोझ डालता है जिसे उचित परिश्रम के साथ काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विवादों के निपटारे और अदालती कार्यवाही के दौरान, दोनों पक्ष अनुबंध के तहत आवश्यक दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। उक्त धारा काम में देरी

और रुकावट से बचने और काम को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। काम पूरा होने तक इंजीनियर से निर्णय लेने के बाद पूरी मेहनत से काम करने का दायित्व ठेकेदार पर होता है। इस प्रकार, अनुबंध के निष्पादन पर जोर दिया जाता है। खंड में प्रयुक्त भाषा विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने की पक्षकारों की मंशा को स्पष्ट नहीं करती है। यह वास्तव में विवादों के समाधान का प्रावधान नहीं करता है। अलग समझौते के खंड 4.1 में कहा गया है कि पक्षकारों और उनके बीच विशेष रूप से सहमति व्यक्त की गई थी कि समझौते से उत्पन्न होने वाले या समझौते की विषय वस्तु को छूने वाले सभी मतभेद या विवाद बैंगलोर में एक सक्षम न्यायालय द्वारा तय किए जाएंगे। खण्ड 48, को खंड 4.1 के संयोजन में पढ़ा जाता है, यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि समझौते में कोई मध्यस्थता खंड नहीं है। उच्च न्यायालय उक्त धारा को मध्यस्थता के प्रावधान पर विचार करके गम्भीर त्रुटि में पड़ गया है। [पैरा 22, 23 और 24] [789-एफ-एच; 790-ए-जी; 791-ई-एफ]

जगदीश चंदर बनाम रमेश चंदर और अन्य। (2007) 5 एससीसी 719: 2007 (5) एससीआर 720- पर निर्भर है।

श्रीमती रुक्मणीबाई गुप्ता बनाम कलेक्टर, जबलपुर एवं अन्य। (1980) 4 SCC 556; उत्तरप्रदेश राज्य बनाम टिप्पर चन्द (1980) 2 एस सी सी 341; दीवान चन्द बनाम जम्मू व कश्मीर राज्य, ए आई आर 1961

जम्मू व कश्मीर 58; रामलाल बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर 1966 पंजाब 436 : 68 पंजाब एल आर 522: आई एल आर (1966) 2 पंजाब 428; उड़ीसा राज्य व अन्य बनाम श्री दामोदर दास ए आई आर 1996 सुप्रीम कोर्ट 942: 1995 (6) पूरक. एससीआर 800; उड़ीसा राज्य और अन्य वी. भाग्यधर दाश (2011) 7 एससीसी 406: 2011 (8) एससीआर 967 -विशिष्ठ।

एम.के. शाह इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1999) 2 एससीसी 594: 1999 (1) एससीआर 419; वेलिंगटन एसोसिएट्स लिमिटेड बनाम किरीट मेहता (2000) 4 एससीसी 272; पंजाब राज्य और अन्य. वी. दीना नाथ (2007) 5 एससीसी 28: 2007 (6) एससीआर 536; मुख्य वन संरक्षक बनाम रतन सिंह एआईआर 1967 एससी 166 1966 पूरक एससीआर 158; गवर्नर-जनरल बनाम शिमला बैंकिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड एआईआर 1947 एल ए एच 215: 226 आईसी 444; के.के. मोदी बनाम के.एन. मोदी और अन्य. (1998) 3 एससीसी 573: 1998 (1) एससीआर 601; एम. दयानंद रेड्डी बनाम ए.पी. इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य। (1993) 3 एससीसी 137: 1993 (2) एससीआर 629; भारत भूषण बंसल बनाम उ.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर एआईआर 1999 एससी 899: 1999 (1) एससीआर 181; बिहार राज्य खनिज विकास निगम एवं अन्य. वी. एनकॉन बिल्डर्स (1) (पी) लिमिटेड (2003) 7 एससीसी 418: 2003 (2) पूरक

एससीआर 812; उड़ीसा राज्य और अन्य वी. भाग्यधर दाश (2011) 7 एससीसी 406: 2011 (8) एससीआर 967- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ:

| | |
|---|---|
| 1999 (1) एससीआर 419 उल्लेख किया गया। | पैरा 6 |
| (2000) 4 एससीसी 272 उल्लेख किया गया। | पैरा 6 |
| 2007 (5) एससीआर 720 निर्भर किया गया। | पैरा 6 |
| (1980) 4 एससीसी 556 विशिष्ट | पैरा 7 |
| 2007 (6) एससीआर 536 उल्लेख किया गया। | पैरा 7 |
| 1966 पूरक एससीआर 158 उल्लेख किया गया। | पैरा 11 |
| (1980) 2 एससीसी 341 विशिष्ट | पैरा 12 |
| 226 आईसी 444 उल्लेख किया गया। | पैरा 13 |
| एआईआर 1961 जे एंड के 58 विशिष्ठ | पैरा 13 |
| ए आई आर 1966 पंजाब 436 विशिष्ठ | पैरा 13 |
| 1995 (6) पूरक एससीआर 800 विशिष्ठ | पैरा 14 |
| 1998 (1) एससीआर 601 उल्लेख किया गया। | पैरा 15 |
| 1993 (2) एससीआर 629 उल्लेख किया गया। | पैरा 15 |
| 1999 (1) एससीआर 181 उल्लेख किया गया। | पैरा 16 |

2003 (2) पूरक एससीआर 812 उल्लेख किया गया। पैरा 17

2011 (8) एससीआर 967 विशिष्ट पैरा 20

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4424/2014

सी.एम.पी. संख्या-7/2013 बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.03.2013 से

के साथ

2014 के सीए संख्या- 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430 और 4431

के.वी विश्वनाथन, एएसजी, एस- श्रीरंगा, बालाजी श्रीनिवासन, मयंक क्षीरसागर, वैशाली दीक्षित, अभिषेक कौशिक, यचिकाकर्ता

दुश्यन्त दवे, श्याम दीवान, एल.एम.चिदानंदय़ा,एस. उदयकुमार सागर, बीना माधवन, प्रसीन ई जोसेफ, शिवेन्द्र सिंह, सिन्हा श्रेय निखिलेश ¼ लोयर्स निट एण्ड कम्पनी के लिए ½ प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा, न्यायाधीश्. द्वारा सुनाया गया।

1. सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई।

2. इन अपीलों में शामिल विवाद, विशेष अनुमति द्वारा प्राथमिकता दी गई, समान होने के कारण, उन्हें एक साथ सुना गया और एक सामान्य

निर्णय द्वारा निपटाया गया। सुविधा के लिए, हम 2013 की विशेष अनुमति याचिका 29011 से उत्पन्न सिविल अपील के तथ्यों को बताएंगे।

3. अपीलकर्ता नंबर 1 एक कंपनी है जो पूरी तरह से कर्नाटक सरकार के स्वामित्व में है और राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता होने के नाते, राज्य में एक लाइसेंसधारी है। इसने दावणगेरे जिले के चन्नागिरी तालुक के तवरेकेरे में 2x8 एमवीए, 66/11 उप-स्टेशनों की स्थापना के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं, जिसमें आंशिक टर्नकी के आधार पर आपूर्ति सामग्री, निर्माण और सिविल कार्य शामिल थे। प्रतिवादी-कंपनी ने बोली में भाग लिया और वह निविदा में सफल रही और तदनुसार, उसे एक आशय पत्र भेजा गया। कुछ प्रक्रियात्मक पहलुओं का सहारा लेने के बाद, अपीलकर्ता-कंपनी और प्रतिवादी के बीच एक अनुबंध किया गया। अनुबंध के निष्पादन के दौरान, प्रतिवादी ने अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 48 के अनुसार इंजीनियर के समक्ष दावा दायर किया और अनुबंध के संबंध में उत्पन्न होने वाले कुछ विवादों को निपटाने के लिए इंजीनियर को बुलाया। चूँकि संबंधित इंजीनियर ने खंड 48.2 के तहत प्रदान की गई तीस दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर कुछ भी नहीं किया, प्रतिवादी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(5) और (6) के तहत 2011 का सीएमपी नंबर 62 (संक्षिप्तता "अधिनियम") मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया।

4. उक्त आवेदन का वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा एकमात्र आधार पर विरोध किया गया था कि खंड 48 मध्यस्थता के लिए प्रदान नहीं करता है और किसी भी परिस्थिति में इसे मध्यस्थता खंड के रूप में नहीं माना जा सकता है। उक्त प्रस्तुतिकरण को प्रमाणित करने के लिए, समझौते के खंड

4.1 पर भरोसा किया गया था। यह कहा गया कि चूंकि कोई मध्यस्थता खंड नहीं है, इसलिए कोई मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश के नामित न्यायाधीश ने डब्ल्यू.पी.क्रमांक 28710/09 (मैसर्स सुभाष प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड बनाम कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में कार्यवाही पर भरोसा रखा जिसका 10.6.2010 को निपटारा किया गया, जिसमें अपीलकर्ता-कंपनी, एक राज्य के स्वामित्व वाली निगम होने के नाते, मध्यस्थता खंड के रूप में खंड 48.2 पर विवाद नहीं किया था। और, उस आधार पर, यह राय दी गई कि विचाराधीन मामले में इसे अस्वीकार करने से रोका गया था। विद्वान नामित न्यायाधीश ने समझौते के खंड 48 और 4.1 की व्याख्या की और माना कि खंड 48 को पढ़ने से यह संकेत मिलेगा कि यह एक मध्यस्थता खंड के विशेषता का हिस्सा है और तदनुसार, विवाद में मामलों का फैसला करने के लिए एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया है।

5. हमने श्री के.वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे और श्री श्याम दीवान को सुना।

6. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विश्वनाथन ने आक्षेपित आदेश की आलोचना करते हुए प्रस्तुत किया है कि समझौते के खंड 48 को मध्यस्थता खंड के रूप में दूर से नहीं समझा जा सकता है और इसलिए, नामित न्यायाधीश गध्यस्थ की नियुक्ति के लिए धारा 11 (5) और (6) के तहत शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उनके द्वारा यह आग्रह किया गया है कि एक रिट याचिका में पारित आदेश, जिसे एक अलग संदर्भ में स्थापित किया गया था, को उक्त खंड को मध्यस्थता खंड के रूप में समझने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि मामले को मध्यस्थ को संदर्भित करने के स्पष्ट इरादे के अभाव में, ऐसे खंड से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, और इससे भी अधिक, जब कोई विशिष्ट खंड 4 अथार्त समझौते में खंड 4 जो विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है, जो यह निर्धारित करता है कि समझौते से उत्पन्न होने वाले या समझौते के विषय-वस्तु को छूने वाले सभी संदर्भ और विवाद बैंगलोर में एक सक्षम न्यायालय द्वारा तय किए जाएंगे। अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए, उन्होंने एम.के. शाह इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1999) 2 एससीसी 594, वेलिंगटन एसोसिएट्स लिमिटेड बनाम किरीट मेहता (2000) 4 एससीसी 272 और जगदीश चंदर बनाम रमेश चंदर और अन्य (2007) 5 एससीसी 719 में दिए गए निर्णयों की और हमारा ध्यान केन्द्रित किया है।

7. सभी अपीलों में प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यन्त दवे और श्री श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया है कि जब खंड 48 को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि पार्टियों का इरादा मामले को मध्यस्थ के पास भेजना है और खंड 4.1 केवल क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का स्थान निर्धारित करता है और इसका मध्यस्थता के लिए किसी भी शर्त से कोई लेना-देना नहीं है। इस बात पर जोर देकर आग्रह किया गया है कि खंड 48 की व्याख्या अधिनियम की धारा 7 में प्रयुक्त भाषा की कसौटी पर की जानी चाहिए और जब उस पर इसकी जांच की जाती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि खंड 48 में एक मध्यस्थता समझौता के सभी गुण और विशेषताएं हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने श्रीमती रुक्मणीबाई गुप्ता बनाम कलेक्टर, जबलपुर और अन्य (1980) 4 एससीसी 556 और पंजाब राज्य और अन्य बनाम दीना नाथ (2007) 4 एससीसी 28 पर निभर्रता  जतायी है। ।

8. इससे पहले कि हम बार में दिए गए अग्रिम प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर ध्यान दें, हम अधिनियम की धारा 7 और इसमें क्या संदेश देते हैं, का संदर्भ लेना उचित समझते हैं और उसके बाद, यह समझने के लिए कि किसी समझौते में मध्यस्थता खंड का गठन क्या होता है, कुछ अधिकारियों का संदर्भ लेते हैं। दो पार्टियों के बीच. अधिनियम की धारा 7 इस प्रकार है:

"7. मध्यस्थता समझौता-

(1) इस भाग में, "मध्यस्थता समझौता" का अर्थ पक्षकारों द्वारा उन सभी या कुछ विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता है जो एक परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हुए हैं या उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे संविदात्मक है या नहीं.

(2) एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है।

(3) मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा।

(4) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि इसमें निहित है -

(ए) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज़;

(बी) पत्रों, टेलेक्स, टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य माध्यमों का आदान-प्रदान जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं; या

(सी) दावे और बचाव के बयान का आदान-प्रदान जिसमें एक पक्षकार द्वारा समझौते के अस्तित्व का आरोप लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है।

(5) किसी अनुबंध में मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ का संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि उस मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बना दिया जाए।"

9. उपरोक्त प्रावधान से, यह स्पष्ट है कि जब तक एक मध्यस्थता समझौता यह निर्धारित नहीं करता है कि पक्षकार उन सभी या कुछ विवादों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं जो उत्पन्न हुए हैं या जो परिभाषित कानूनी संबंधों के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे संविदात्मक हों या नहीं, तब तक कोई मध्यस्थता समझौता नहीं हो सकता है। एक मध्यस्थ का संदर्भ. विस्तृत रूप से कहें तो, यह बताता है कि विवादों को मध्यस्थ के पास भेजने के लिए सर्वसम्मति से स्वीकृति व्यक्त करने का इरादा होना चाहिए। किसी समझौते में मध्यस्थता खंड की अनुपस्थिति में, जैसा कि धारा 7 की उपधारा (4) में परिभाषित किया गया है,। पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद/विवाद को विवाद के निर्णय के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास नहीं भेजा जा सकता है।

10. श्रीमती रुक्मणीबाई गुप्ता (सुप्रा) ने समझौते के खंड 15 पर विचार करते हुए, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी कि यह खंड पक्षकारों के बीच एक मध्यस्थता समझौते का वर्णन करता है। उक्त धारा इस प्रकार थी:-

"जब भी इसके बाद उक्त भूमि से जुड़े किसी भी मामले या चीजों या उसके कामकाज या गैर-कार्य या किसी किराए या रॉयल्टी की राशि या भुगतान को लेकर कोई संदेह, मतभेद या विवाद उत्पन्न होगा। या इस मामले में यहां देय अंतर का निर्णय पट्टादाता द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।"

विद्वान न्यायाधीशों ने, उक्त खंड के अर्थ और आशय की सराहना करने के लिए, 1940 के अधिनियम की धारा 2 (ए) को सन्दर्भित किया है और रसेल ऑन आर्बिट्रेशन के 19 वें संस्करण... पी. 59 से एक अंश को पुनः प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है: -

"अगर समझौते की शर्तों से यह प्रतीत होता है कि किसी मामले को किसी व्यक्ति के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो पक्षकारों का इरादा यह था कि वह न्यायिक जांच की प्रकृति में जांच करें और पक्षकारों के संबंधित मामलों को सुनें और निर्णय लें उसके सामने रखे गए सबूतों पर, मामला मध्यस्थता में से एक है"

11. न्यायालय ने मुख्य वन संरक्षक बनाम रतन सिंह ए.आई.आर. 1967 एस सी 166:1966 पूरक एस सी आर 158 का भी हवाला दिया और फैसला सुनाया कि:

"चर्चा के तहत खंड में विवादों को पट्टेदार को संदर्भित करने का प्रावधान है और पट्टेदार के निर्णय को अंतिम माना जाता है। इसके वास्तविक निर्माण पर यह एक मध्यस्थता समझौते का वर्णन करता है"

12. इस समय, यूपी राज्य में तीन न्यायाधीशों की एक पीठ के फैसले का उल्लेख करना उचित है। स्टेट आॅफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम टिपर चंद' (1980)2 एस सी सी 341 जहां न्यायालय समझौते में खंड 22 की व्याख्या कर रहा था, जो विचाराधीन था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसमें मौजूद शर्तों में मध्यस्थता खंड का उल्लेख है। उक्त मामले में शामिल खण्ड इस प्रकार है:-

"अनुबंध में अन्यथा निर्दिष्ट होने के अलावा, कुछ समय के लिए अधीक्षण अभियंता का निर्णय यहां उल्लिखित विनिर्देशों, डिजाइन, ड्राइंग और निर्देशों के अर्थ से संबंधित सभी प्रश्नों पर अनुबंध के सभी पक्षों पर अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा। कारीगरी की गुणवत्ता, या काम में उपयोग की जाने वाली सामग्री, या किसी भी अन्य प्रश्न, दावे, अधिकार, मामले या चीजों के बारे में, किसी भी तरह से अनुबंध, डिजाइन, ड्राइंग से उत्पन्न होने वाले या संबंधित के बारे में ऐसे इंजीनियर का निर्णय विनिर्देश,

अनुमान, निर्देश, आदेश, या ये शर्तें, या अन्यथा कार्यों से संबंधित, या निष्पादन या इसे निष्पादित करने में विफलता, चाहे कार्य की प्रगति के दौरान उत्पन्न हो, या ठेकेदार द्वारा अनुबंध के पूरा होने या त्यागने के बाद उत्पन्न हो, यह भी अंतिम, निर्णायक और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।"

उक्त खंड की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने इस प्रकार राय दी:-

"माना जाता है कि खंड में कोई स्पष्ट मध्यस्थता समझौता शामिल नहीं है। न ही इस तरह के समझौते को इसकी शर्तों से निहितार्थ द्वारा वर्णित किया जा सकता है, इसमें किसी भी विवाद का कोई उल्लेख नहीं है, उसके संदर्भ का तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी ओर, उद्देश्य यह खंड स्पष्ट रूप से अधीक्षण अभियंता को कार्य के निष्पादन की निगरानी और समय-समय पर प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार देता प्रतीत होता है।"

13. इस संदर्भ में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने गवर्नर-जनरल बनाम सिमला ए आई आर 1947 एल ए एच 215: 226. आई सी 444 में उच्च न्यायालयों के फैसले को मंजूरी दे दी। बैंकिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, दीवान चंद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य ए आई आर 1961 जे एण्ड के 58 और राम लाल बनाम पंजाब राज्य ए आई आर 1966 पंजाब

436:68 पंजाब एल आर 522: आई एल औ आर (1966) 2 पंजाब 428 जिसमें धाराएं अलग थीं। उस संदर्भ में, यह राय थी कि उच्च न्यायालयों ने मध्यस्थता प्रदान करने वाले खंड की सही व्याख्या की थी। हम विद्वान न्यायाधीशों द्वारा किये गये चित्रण को पुन: प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:-

> "जम्मू और कश्मीर मामले में प्रासंगिक खंड इन शर्तों में शामिल किया गया था:
>
> "ठेकेदार और विभाग के बीच किसी भी विवाद के लिए मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी जम्मू और कश्मीर का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।"

इस खंड की भाषा वर्तमान मामले के खंड से भौतिक रूप से भिन्न है और हमारी राय में मध्यस्थता समझौते के बराबर इसकी सही व्याख्या की गई है। इस संबंध में "ठेकेदार और विभाग के बीच कोई विवाद" शब्दों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। राम लाल मामले की धारा के बारे में भी यही सच है जो इस प्रकार है:

> "विवाद की स्थिति में मामला सर्कल के अधीक्षण अभियंता को भेजा जाएगा, जिनका आदेश अंतिम होगा।"
>
> हमें शायद ही यह कहने की ज़रूरत है कि यह खंड न केवल अनुबंध के पक्षों के बीच विवाद को संदर्भित करता है, बल्कि

विशेष रूप से अधीक्षण अभियंता के संदर्भ का भी उल्लेख करता है और इसलिए इसे मध्यस्थता समझौते के रूप में सही ढंग से समझा जाना चाहिए।"

14. इस स्तर पर, उड़ीसा राज्य और अन्य आदि बनाम श्री दामोदर दास ए आई आर 1996 एस सी 942 मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जिसमें न्यायालय ने सवाल उठाया था कि क्या विवादों के समाधान के लिए कोई समझौता था जैसा कि इसमें निहित है।

समझौते का खंड 25. उक्त धारा इस प्रकार है:-

"25. सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंता का निर्णय अंतिम होगा।- इस अनुबंध में अन्यथा निर्दिष्ट होने के अलावा, फिलहाल सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंता का निर्णय अंतिम, निर्णायक और अनुबंध से संबंधित सभी प्रश्नों पर अनुबंध के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यहां पहले उल्लिखित विशिष्टताओं, रेखाचित्रों और निर्देशों का अर्थ और कारीगरी की गुणवत्ता या काम में प्रयुक्त सामग्री के बारे में, या किसी भी अन्य प्रश्न, दावे, अधिकार, मामले या चीज़ के बारे में, जो भी किसी भी तरह से उत्पन्न हो, या संबंधित हो, अनुबंध, ड्राइंग, विनिर्देश, अनुमान, निर्देश, आदेश या इन

शर्तों, या अन्यथा कार्यों या निष्पादन या इसे निष्पादित करने में विफलता से संबंधित, चाहे कार्य की प्रगति के दौरान या अनुबंध पूरा होने के बाद या उसके शीघ्र निर्धारण के दौरान उत्पन्न हो ।"

तीन जजों की बेंच ने टिपर चंद (सुप्रा) में बताए गए सिद्धांतों का उल्लेख किया और इस प्रकार कहा: -

"हम उपरोक्त अनुपात के साथ सम्मानजनक समझौते में हैं। यह स्पष्ट है कि अनुबंध के दो पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद के समाधान के लिए, समझौते को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा, उसमें नामित मध्यस्थ या अन्यथा का संदर्भ प्रदान करना होगा। किसी भी विवाद या मतभेद और इसकी अनुपस्थिति में पार्टियों के बीच अनुबंधित विवाद या मतभेद को हल करने के लिए मध्यस्थता के संदर्भ में ऐसे समझौते के अस्तित्व को बताना मुश्किल है। श्रीमती रुक्मणीबाई गुप्ता बनाम कलेक्टर में अनुपात प्रतिवादी की सहायता नहीं करता है ।"

15. के.के. में. मोदी बनाम के.एन. मोदी और अन्य (1998) 3 एससीसी 573, दो-न्यायाधीशों की पीठ समझौते के खंड 9 की व्याख्या कर रही थी जो इस प्रकार है:-

> "कार्यान्वयन वित्तीय संस्थानों के परामर्श से किया जाएगा। इस समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में सभी विवादों, स्पष्टीकरण आदि के लिए, इसे अध्यक्ष, आईएफसीआई या उनके नामांकित व्यक्तियों को भेजा जाएगा, जिनके निर्णय अंतिम और दोनों समूह के लिए बाध्यकारी होंगे।"

अदालत ने रसेल ऑन आर्बिट्रेशन के 21वें संस्करण 37, पैरा 2-014 के एक अंश का उल्लेख किया है और रुक्मणीबाई गुप्ता (सुप्रा) और एम. दयानंद रेड्डी बनाम ए.पी. इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य (1993) एससीसी 137 में निर्णय और यह माना गया कि उक्त खंड एक मध्यस्थता खंड नहीं था और इसलिए, अध्यक्ष के समक्ष कार्यवाही , आईएफसीआई को मध्यस्थता कार्यवाही के रूप में नहीं माना जा सकता था। इसे निम्नलिखित आधार पर आयोजित किया गया था:-

> "निस्संदेह, आईएफसीआई के अध्यक्ष के साथ ग्रुप ए और बी के विभिन्न सदस्यों द्वारा किए गए पत्राचार के

दौरान, कुछ सदस्यों ने खंड 9 के संबंध में "मध्यस्थता" शब्द का इस्तेमाल किया है।

हालांकि, यह अपने आप में निर्णायक नहीं है। पार्टियों का इरादा अध्यक्ष, आईएफसीआई के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कोई न्यायिक निर्धारण करने का नहीं था। न ही अध्यक्ष, आईएफसीआई को अपना निर्णय केवल पार्टियों द्वारा उनके समक्ष रखी गई सामग्री और उनकी प्रस्तुतियों के आधार पर लेने की आवश्यकता थी। वह अपनी स्वयं की पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र था: उसे अपना दिमाग लगाना था और इस उद्देश्य के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करना था। वह अन्य विशेषज्ञों की मदद लेने के लिए स्वतंत्र था। उसे मूल्यांकन और संपत्ति के विभाजन के प्रश्न पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी एक विशेषज्ञ और मध्यस्थ के रूप में नहीं। उसे अपने स्थान पर किसी अन्य को नामित करने के लिए अधिकृत किया गया है। लेकिन अनुबंध इंगित करता है कि उसे एक विशेषज्ञ को नामित करना होगा। तथ्य यह है कि आईएफसीआई के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुतियाँ की गई थीं, इससे निर्णय लेने में कोई बदलाव नहीं आएगा मध्यस्थता में प्रक्रिया करें।"

16. भारत भूषण बंसल बनाम यू.पी. लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर" में, समझौते के खंड 23 और 24 को मध्यस्थता खंड की नींव बनाने के लिए पेश किया गया था। यह इस प्रकार है: -

"कुछ मामलों पर यूपीएसआईसी के कार्यकारी अभियंता का निर्णय अंतिम होगा।

23. अनुबंध में अन्यथा निर्दिष्ट होने के अलावा, कार्यकारी अभियंता का निर्णय अंतिम, निर्णायक और अनुबंध के दोनों पक्षों के लिए यहां उल्लिखित अर्थ, विनिर्देश, डिजाइन, चित्र और निर्देशों से संबंधित सभी प्रश्नों पर बाध्यकारी होगा, और कार्य में उपयोग की गई कारीगरी या सामग्री की गुणवत्ता या डिज़ाइन, ड्राइंग, विनिर्देशों, अनुमानों, निर्देशों, आदेशों या अन्यथा कार्यों या निष्पादन या विफलता से संबंधित किसी भी अन्य प्रश्न के संबंध में चाहे कार्य की प्रगति के दौरान, या उसके पूरा होने के बाद या ठेकेदार द्वारा अनुबंध छोड़ने के बाद उत्पन्न हो, उसे निष्पादित करना अंतिम और निर्णायक होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

अन्य सभी मामलों पर यूपीएसआईसी के एमडी का निर्णय अंतिम होगा

24. इसके खंड 23 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, किसी भी दावे, अधिकार, मामले या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाली चीज़ से संबंधित सभी प्रश्नों पर यूपीएसआईसी के प्रबंध निदेशक का निर्णय अनुबंध के दोनों पक्षों के लिए अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा। अनुबंध से संबंधित या इन शर्तों से संबंधित या ठेकेदार द्वारा अनुबंध के परित्याग से संबंधित और इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले अन्य सभी मामलों के संबंध में और यहां विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।"

उक्त खंडों की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार राय दी: -

"वर्तमान मामले में, खंड 23 और 24 को एक साथ पढ़ने पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुबंध से जुड़े किसी भी दावे या अधिकार, मामले या चीज से उत्पन्न या उससे संबंधित प्रश्नों के संबंध में, जबकि कुछ प्रकार के दावों के संबंध में कार्यकारी अभियंता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। प्रश्न, शेष दावों के संबंध में प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी है। कार्यकारी अभियंता और प्रबंध निदेशक दोनों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी जांच और सामग्री के आधार पर प्रश्न या दावे

का निर्धारण करें। इनमें से कोई भी खंड मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत आने वाली पूर्ण मध्यस्थता पर विचार नहीं करता है।"

17. बिहार राज्य खनिज विकास निगम और अन्य बनाम एनकॉन बिल्डर्स (1) (पी) लिमिटेड (2003) 7 एससीसी 418 में, अधिनियम के तहत एक मध्यस्थता समझौते के मध्यस्थता खंड से निपटते समय न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"(1) किसी चिंतनीय मामले के संबध में वर्तमान या भविष्य में मतभेद होना चाहिए।

(2) निजी न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे मतभेदों को निपटाने का पार्टियों का इरादा होना चाहिए।

(3) पार्टियों को ऐसे न्यायाधिकरण के निर्णय से बाध्य होने के लिए लिखित रूप में सहमत होना होगा।

(4) पार्टियों को एड इडेम होना चाहिए"।

उक्त मामले में, यह भी राय दी गई है कि अधिनियम मध्यस्थता समझौते के किसी भी रूप को निर्धारित नहीं करता है। समझौते में 'मध्यस्थता' शब्द का विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है वह पार्टियों के इरादे को इकट्ठा करना है कि क्या वे मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए सहमत हैं।

18. दीना नाथ (सुप्रा) में, समझौते का खंड इस प्रकार है: -

"4. विभाग और ठेकेदार/सोसाइटी के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को आदेश के लिए अधीक्षण अभियंता, आनंदपुर साहिब, हाइडल (निर्माण) सर्कल नंबर 1, चंडीगढ़ को भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य/बाध्यकारी होगा। ।"

दो-न्यायाधीशों की पीठ, जो मूल रूप से टिपर चंद (सुप्रा) पर निर्भर थी, जिसने दीवान चंद (सुप्रा) में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी थी, ने उपरोक्त खंड को मध्यस्थता प्रदान करने वाला माना क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से "विवाद" शब्द का उल्लेख किया गया था। अधीक्षण अभियंता को भेजा जाएगा और आगे कहा जाएगा कि उनका निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों को स्वीकार्य/बाध्यकारी होगा।

19. जगदीश चंदर (सुप्रा) में, न्यायालय ने पहले के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, "मध्यस्थता समझौते" शब्द के संबंध में कुछ सिद्धांत निकाले। उक्त सिद्धांत मूल रूप से कुछ मुख्य पहलुओं पर जोर देते हैं, अर्थात्,

(i) हालांकि मध्यस्थता समझौते का कोई विशिष्ट रूप नहीं है, फिर भी समझौते की शर्तों से एकत्र किए जा सकने वाले पक्षों के इरादे को एक दृढ़ संकल्प और दायित्व का खुलासा करना चाहिए

(ii) "मध्यस्थता" और "मध्यस्थता न्यायाधिकरण" या "मध्यस्थ" शब्दों का गैर-उपयोग किसी खंड को मध्यस्थता समझौते के रूप में व्याख्या करने से अलग नहीं करेगा यदि मध्यस्थता समझौते के गुण या तत्व स्थापित हैं, यानी,

(ए) समझौता लिखित में होना चाहिए.

(बी) पार्टियों को उनके बीच किसी भी विवाद (वर्तमान या भविष्य) को निजी न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए संदर्भित करने के लिए सहमत होना चाहिए था।

(सी) निजी न्यायाधिकरण को निष्पक्ष तरीके से विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिससे पक्षों को उसके समक्ष अपना मामला रखने का उचित अवसर मिल सके।

(डी) पार्टियों को इस बात पर सहमत होना चाहिए कि विवादों के संबंध में निजी न्यायाधिकरण का निर्णय उन पर बाध्यकारी होगा; और

(iii) जहां मध्यस्थता समझौते की किसी भी विशेषता का विशिष्ट बहिष्कार होता है या इसमें कुछ भी शामिल होता है जो मध्यस्थता समझौते से अलग होता है, यह मध्यस्थता समझौता नहीं होगा। इस संदर्भ में, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कुछ उदाहरण दिए हैं और हमें लगता है कि उन्हें पुनः प्रस्तुत करना उचित है: -

"उदाहरण के लिए, जहां किसी समझौते के लिए प्राधिकरण को किसी दावे या विवाद को बिना सुनवाई के तय करने की आवश्यकता होती है या अनुमति देती है, या प्राधिकरण को केवल एक पक्ष के हित में कार्य करने की आवश्यकता होती है, या यह प्रावधान करता है कि प्राधिकरण का निर्णय अंतिम नहीं होगा और पार्टियों पर बाध्यकारी, या यदि कोई भी पक्ष प्राधिकरण के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह राहत के लिए नागरिक मुकदमा दायर कर सकता है, इसे मध्यस्थता समझौता नहीं कहा जा सकता है।"

20. उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम भाग्यधर दास (2011)7 एस सी सी 406 में, न्यायालय ने मध्यस्थता समझौते के गठन के लिए एक विशेष फॉर्म की गैर-आवश्यकता और मध्यस्थता के संदर्भ के इरादे का पता लगाने के बारे में चर्चा करते हुए, जैसा कि रुक्मणीबाई गुप्ता (सुप्रा),में कहा गया है इस प्रकार देखा गया: -

"16. जबकि हम ऊपर बताए गए सिद्धांत से सम्मानपूर्वक सहमत हैं, हमें इस बात पर संदेह है कि क्या रुक्मणीबाई गुप्ता मामले में विचार किया गया खंड एक मध्यस्थता समझौता होगा यदि उक्त निर्णय में उल्लिखित

सिद्धांत और बाद के निर्णय में उल्लिखित परीक्षण होंगे दामोदर दास मामले में बड़ी पीठ को लागू किया जाता है। जैसा भी हो। वास्तव में, दामोदर दास मामले में बड़ी पीठ ने स्पष्ट रूप से माना कि रुक्मणीबाई गुप्ता मामले में निर्णय उसमें विचार किए गए खंड के विशेष शब्दों पर तय किया गया था: (दामोदर दास मामला, एससीसी पी) 224, पैरा 11)

"11....रुक्मणीबाई गुप्ता बनाम कलेक्टर में अनुपात प्रतिवादी की सहायता नहीं करता है। वहां की भाषा से इस न्यायालय ने, निहितार्थ से, मध्यस्थता के लिए विवाद या मतभेद के अस्तित्व का अनुमान लगाया।"

21. इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त प्राधिकारियों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कि किन परिस्थितियों में किसी समझौते में एक खंड को मध्यस्थता समझौते के रूप में समझा जा सकता है, वर्तमान में समझौते के खंड 48 को संदर्भित करना उचित है। उक्त खंड इस प्रकार है:-

"48.0 विवादों का निपटारा:

48.1 अनुबंध के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद को, जहां तक संभव हो, पार्टियों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाएगा।

48.2 यदि कार्य के निष्पादन के लिए अनुबंध से उत्पन्न होने वाले मालिक और ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, चाहे कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरा होने के बाद या समाप्ति से पहले या बाद में, परित्याग या अनुबंध का उल्लंघन होने पर, सबसे पहले, इसे इंजीनियर द्वारा संदर्भित और निपटारा किया जाएगा, जो किसी भी पक्ष द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किए जाने के बाद तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, इसकी लिखित सूचना मालिक और ठेकेदार को देगा।

48.3 जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है, को छोड़कर, निर्दिष्ट प्रत्येक मामले के संबंध में ऐसा निर्णय अंतिम होगा और काम पूरा होने तक पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और ठेकेदार द्वारा इसे तुरंत प्रभावी किया जाएगा जो सभी उचित परिश्रम के साथ काम को आगे बढ़ाएगा।

48.4 विवादों के निपटारे और अदालती कार्यवाही के दौरान, दोनों पक्ष अनुबंध के तहत अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य होंगे।"

22. उक्त खंड को ध्यान से पढ़ने पर, यह प्रदर्शित होता है कि यह पक्षकारों को अनुबंध के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रावधान करता है। यह पहला भाग है. दूसरा भाग, जैसा कि स्पष्ट है, वह है जब कार्यों की प्रगति के दौरान या उसके पूरा होने के बाद या समाप्ति, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में कार्यों के प्रदर्शन से संबंधित अनुबंध के पक्षों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद या मतभेद उत्पन्न होते हैं। अनुबंध के संबंध में, इसे इंजीनियर द्वारा संदर्भित और निपटान किया जाना है, जो किसी भी पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने पर, मालिक और ठेकेदार को तीस दिनों के भीतर अपने निर्णय की सूचना देगा। एक शर्त यह भी है कि निर्दिष्ट प्रत्येक मामले के संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा और कार्य पूरा होने तक पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और आवश्यक होगा ठेकेदार द्वारा इसे प्रभावी किया जाएगा जो उचित परिश्रम के साथ काम को आगे बढ़ाएगा। पक्षकारों की मंशा को समझने के लिए खंड का यह हिस्सा महत्वपूर्ण है। इस अभिधारणा का अध्ययन करने पर, यह चित्रात्मक रूप से स्पष्ट है कि यह ऐसी कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है जो दूर से संकेत दे कि संबंधित इंजीनियर को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए न्यायिक रूप से एक निर्णायक के रूप में कार्य करने या दोनों दलों की प्रस्तुतियों पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इंजीनियर का निर्णय केवल कार्य पूरा होने तक बाध्यकारी होता है। यह केवल ठेकेदार पर बोझ डालता

है जिसे उचित परिश्रम के साथ काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त के अलावा, विवादों के निपटारे और अदालती कार्यवाही के दौरान, दोनों पक्ष अनुबंध के तहत आवश्यक दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। जैसा कि हम समझते हैं, उक्त खंड काम में देरी और रुकावट से बचने और काम को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि काम पूरा होने तक इंजीनियर से निर्णय लेने के बाद काम को पूरी लगन से करने का दायित्व ठेकेदार पर होता है। इस प्रकार, अनुबंध के निष्पादन पर जोर दिया जाता है। खंड में प्रयुक्त भाषा विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने की पार्टियों की मंशा को स्पष्ट नहीं करती है। यह वास्तव में विवादों के समाधान का प्रावधान नहीं करता है।

23. उपरोक्त के अलावा, समझौते का खंड 4.1 ध्यान देने योग्य है। यह इस प्रकार है:-

> "4.1 पक्षकारों द्वारा और उनके बीच विशेष रूप से सहमति व्यक्त की गई है कि समझौते से उत्पन्न होने वाले या समझौते के विषय को छूने वाले सभी मतभेद या विवाद, बैंगलोर में एक सक्षम न्यायालय द्वारा तय किए जाएंगे।"

24. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विश्वनाथन ने इस पर अत्यधिक जोर देते हुए प्रस्तुत किया है कि उक्त खंड न केवल बैंगलोर में

एक सक्षम न्यायालय का बताकर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, बल्कि संक्षेप में और वास्तव में, यह निर्धारित करता है कि सभी मतभेद या समझौते के विषय-वस्तु से संबंधित समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय बैंगलोर में एक सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दवे का कहना है कि यह केवल बेंगलुरु की सक्षम अदालत को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान करता है और इससे परे इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। यदि श्री दवे की प्रस्तुति की उचित सराहना की जाती है, तो यह बताया जाएगा कि यदि मध्यस्थ द्वारा कोई पुरस्कार पारित किया जाता है, तो अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत अन्य सभी कार्यवाही बैंगलोर में सक्षम न्यायालय में शुरू की जानी चाहिए। यह निर्माण, हमारी राय में, उक्त खंड पर नहीं रखा जा सकता है। इसका वास्तव में अर्थ यह है कि विवादों और मतभेदों का निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना बाकी है। इस प्रकार, खंड 48, जैसा कि हमने विश्लेषण किया है, खंड 4.1 के साथ संयोजन में पढ़ा जाता है, स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि समझौते में कोई मध्यस्थता खंड नहीं है। जिन खंडों की व्याख्या मध्यस्थता खंड के रूप में की गई थी, जैसा कि राम लाल (सुप्रा) और दीवान चंद (सुप्रा) में किया गया है, जिन्हें टिपर चंद (सुप्रा) में अनुमोदित किया गया है, उन्हें अलग-अलग तरीके से जोड़ा गया है। जहां तक रुक्मणीबाई गुप्ता (सुप्रा) का सवाल है, जैसा कि दामोदर दास (सुप्रा) और भाग्यधर दास (सुप्रा) में भी कहा गया है, इसे

अपने तथ्यों पर निर्भर रहना होगा। दीना नाथ (सुप्रा) में उपवाक्य को अलग तरह से दर्शाया गया है, और खंड 48, जिस पर हम काम कर रहे हैं, में इसके साथ कोई समानता नहीं है। वास्तव में, खंड 48, भले ही इसे बढ़ाया जाए, को मध्यस्थता खंड नहीं माना जा सकता है। मध्यस्थता खंड का गठन करने वाले तत्व और गुण, जैसा कि जगदीश चंदर (सुप्रा) में कहा गया है, अनुपस्थित हैं। इसलिए, अकाट्य निष्कर्ष यह है कि उच्च न्यायालय ने उक्त खंड को मध्यस्थता के प्रावधान के रूप में मानकर गंभीर त्रुटि की है।

25. परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री राजेश शर्मा, द्वितीय (आर.एच.जे.एस. विशिष्ठ न्यायाधीश, सेशन न्यायालय (भ्र.नि.अधि.), अजमेर द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।